को स्विच ट्रेड कहा जाता है वह हो रहा है ? और अगर हो रहा है पूर्वी योरप के देशों द्वारा तो इस को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? ।

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : बच्चा जूट का कोई निर्यात एस० टी० सी० के जरिए नहीं होता ।

श्री मधु लिमये : स्विच ट्रेड ? सूती कपड़े के बारे में और जूट के बारे में स्विच ट्रेड ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : एस० टी० सी० न सूती कपड़ा बाहर भेजता है और न जूट भेजता है ।

श्री मधु लिमये : स्विच ट्रेड का जवाब ही नहीं दे रहे हैं ।

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : This switch-trade is linked up, because there is an allegation that switch-trade is going on in East-European countries. STC is not exporting jute nor cotton textiles, so the question of switch-trade does not arise.

Non-Banking Companies

*544. SHRI GEORGE FERNANDES : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of non-banking industrial and commercial companies that have been permitted to accept short and long term deposits to meet their financial needs ;

(b) the total amount deposited with such firms as on the 31st March, 1967 and the interest rates offered on these amounts ;

(c) whether any of the firms which were allowed to accept such deposits have gone into liquidation ;

(d) whether complaints have been received about non-receipt of interest and capital from some of these firms on the due dates ; and

(e) if so, whether Government contemplate to take effective measures to safeguard the interests of the depositors with such firms ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATH REDDI) : (a) The non-banking companies do not require prior permission to accept deposits from the public.

(b) According to returns received by the Reserve Bank of India from the non-banking non-financial companies, 1569 companies held deposits aggregating Rs. 160·23 crores at the end of March, 1965. Information for later periods can be available only when the Reserve Bank receives and compiles the returns. The rate of interest varied between 5 and 12 per cent per annum.

(c) According to present information available with the Department, three such companies have gone into liquidation.

(d) Yes, Sir.

(e) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1915/67].

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : जब मुल्क में बैंकिंग का व्यापार करने वाली काफ़ी संस्थायें हैं, सरकार का स्टेट बैंक आफ़ इण्डिया भी है और इस वक्त जब कि बैंकिंग के सम्बन्ध में कभी राष्ट्रीयकरण, कभी सामाजिक नियन्त्रण—इस किस्म की बातें चलती हैं—तो फिर इन 50–60 कम्पनियों को 150 करोड़ रुपया 5 फीसदी से 12 फीसदी ब्याज पर जमा करने की इजाजत क्यों दी जाती है और सरकार इस फैसले पर क्यों नहीं आ रही है कि जो असल में बैंकिंग का व्यापार करने वाली कम्पनियां नहीं हैं, उन को इस ढंग से पैसा जमा करने की इजाजत न दी जाय ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं तो यह समझता हूं कि खास कर ऐसे कामों में जैसे हायर परचेज सिस्टम के लिये अगर दूसरी इंस्टीचूशन्ज से रुपया मिलने में दिक्कत हो तो कोई एतराज होना न चाहिए ।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : मैंने हायर परचेज की बात नहीं कही है । जैसे इण्डियन एक्स-

प्रेस 11 परसेन्ट पर रुपया मांग रहा है, तो वह अखबार की हायर परचेज के लिये नहीं मांग रहा है, इसी तरह से इन्जनियरिंग कम्पनीज हैं, प्लास्टिक कम्पनीज हैं, दूसरी कम्पनियां हैं, वे बैंकों के पास न जा कर लोगों से पैसा मांगते हैं, क्योंकि बैंकों में उन को सिक्योरिटी या शोयरटी देनी पड़ती है—यहां इस दृष्टि से जरूरत नहीं पड़ती है? इसलिये मैं चाहता हूं कि इस का साफ उत्तर आ जाय, तय मैं दूसरा प्रश्न पूछूं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: यह तो एतबार की बात है, लोगों को उन पर एतबार है और जब इण्डस्ट्रीयल डेवलपेन्ट के लिये पैसे की जरूरत है, दूसरी जगह से उन को नहीं मिलता है—तो यह नहीं समझ में आता कि इस जरिये से जब रुपया मिल सकता है, उस पर एतराज क्यों किया जाता है।

श्री जार्ज फर्नेन्डीज: अभी मंत्री महोदय ने यहां पर उत्तर दिया कि 50–60 कम्पनियों के पास करीबन 150 करोड़ रुपया है। इन में से तीन कम्पनियां लिक्वीडेशन में है—क्या इस की उन को जानकारी है, क्या उन के पास इस की कोई शिकायत आई है कि दिल्ली की एक कम्पनी के पास बम्बई के 100 लोगों ने पैसा जमा कराया था और जब साल भर पूरा हो गया तो कम्पनी लिक्वीडेशन में चली गई। जब लोग कम्पनी से अपना पैसा मांगते हैं तो कम्पनी की ओर से उन की चिट्ठियों का जवाब तक नहीं जाता है। ऐसी स्थिति में आप उन कम्पनियों को पैसा लेने के लिये क्यों इजाजत देते हैं।

अभी मंत्री महोदय ने जो नियम सदन के पटल पर रखे हैं, उस में एक्जेम्पशन देने का नियम भी है—

> "The Reserve Bank may, if it considers it necessary for avoiding any hardship or for any other just and sufficient reason, grant extensions of time to comply with, or exempt any company or class of companies from, all or any of the provisions of this directive".

तो इस का मतलब यह हो गया कि जो भी नियन्त्रण लगाया, उसमें उन के लिये पहले से छूट की व्यवस्था कर दी गई है। तो जब आप ऐसा कोई निर्णय लेने के लिये तैयार नहीं हैं तो क्या आप ऐसी कोई कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं कि जिससे वह पैसा जो वहां जमा किया जाता है उस का कोई बीमा ही सके, ताकि यदि कम्पनी विगड़ जाय तो लोगों को उनका पैसा वापस मिल सके? दूसरे ऐसी कम्पनियों के डाइरेक्टरों के खिलाफ़ सख्त कानूनी कार्यवाही कर के उन के ऊपर चीटिंग का आरोप लगा कर, उन्हें सीधे जेल भेजने की व्यवस्था के लिए तैयार हैं?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: पहले तो मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जिसमें कहा गया कि 160 करोड़ रुपया सिर्फ 50 कम्पनियों के पास है। यह गलत है—हमने जो फिगर बताई है वह 1569 है, 50 कम्पनियों का इस में कोई सवाल नहीं है।

दूसरे जहां तक रिजर्व बैंक का ताल्लुक है, उन्होंने डाइरेक्टिव्ज दे रखी हैं कि कम्पनियों को किन-किन हिदायत के मातहत काम करना है। अगर वे उन डाइरैक्टिव्ज के मातहत काम नहीं करती हैं तो रिजर्व बैंक के इंस्पैक्शन के बाद या जब हमारे पास शिकायतें आती हैं तो इंस्पैक्शन के बाद जब यह मालूम होता है कि उन्होंने किसी डाइरैक्टिव को तोड़ा है तो उन के खिलाफ़ कार्यवाही की जाती है, उन के खिलाफ़ क्रिमनल-केस भी अगर जरूरत होती है तो किया जाता है।

SHRI S. S. KOTHARI: There are two aspects of the problem. One aspect is, as pointed out by Shri Fernandes, that there are certain companies which indulge in this sort of cheating and that they should be strictly dealt with. There is another aspect and that is the genuine leading industrial companies require loans for their ordinary industrial operations. The restrictions affect industrial activity. If they are unable to obtain sufficient advances

MR. SPEAKER : What he has said you are repeating ; you are supporting the Government.

SHRI S. S. KOTHARI : Has the Government ascertained that genuine industrial activity is being adversely affected ? The restrictions which have been laid down by the Reserve Bank should be relaxed. That is my point. The relaxation is necessary in genuine cases.

SHRI F. A. AHMED : So far as the restrictions imposed by the Reserve Bank are concerned, they are to the advantage of industries requiring financial assistance from such companies. As far as the malpractices indulged in by some of the companies are concerned, whenever any such practice is brought to our notice or to the notice of the Reserve Bank, action is taken and, in some cases, even criminal cases have been filed.

श्री ओंकार लाल बेरवा : दिल्ली में ऐसी कितनी कम्पनियों का आपने चालान किया है, जिन्होंने हायर-परचेज के नाम से चीटिंग की है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी कम्पनियां हैं और कितनों का चालान किया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : 8 कम्पनीज के खिलाफ क्रिमनल केसेज पेन्डिंग हैं।

PRECISION INSTRUMENT PROJECT, PALGHAT

+

*546. SHRI C. CHAKRAPANI :
SHRI A. K. GOPALAN :
SHRI E. K. NAYANAR :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a project in the public sector to manufacture precision instruments at Pudussery, Palghat district, Kerala has been sanctioned ;

(b) if so, the amount sanctioned for the project during the Fourth Plan ; and

(c) the reasons for not completing the project during the Third Plan period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATH REDDI): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The Detailed Project Report for setting up a Mechanical Instruments Plant at Pudussery, Palghat by Instrumentation Ltd., Kota (a public sector unit), with assistance from U.S.S.R., received from Prommash export, Moscow was approved by Government in August, 1966. This Project estimated to cost about Rs. 9 crores was expected to be completed in 1970. A provision of Rs. 13·2 crores has been included in the draft outline of the Fourth Plan for investment in instrumentation Ltd., Kota towards the two projects at Kota and at Palghat. The committed expenditure upto the end of March, 1967 on Palghat Project alone is of the order of Rs. 32 lakhs.

SHRI C. K. CHAKRAPANI : It is reported in the press that there is a move to shift the project from Kerala to some other place. May I know whether there is any such move ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS : (SHRI F. A. AHMED) : There is no such proposal.

SHRI C. K. CHAKRAPANI : The projects at Kota and Palghat have been approved. I do not know why there is delay in the completion of the projects. When does the Government expect to complete these projects ?

SHRI F. A. AHMED : The idea was to start these two projects, one at Kota and another at Palghat. According to the present arrangement, because of the demand and also because of the fact that the Kota project, which has already been started, and which will go into production next year, if some additional amount is spent on that project it will be more economical than to invest in another project. That is why for the present, till the situation improves and the resources are available, the project in Kerala has been postponed.

SHRI VASUDEVAN NAIR : The statement of the Minister really causes a lot of concern to the people of my State because we have had such experiences in the past also. I should like to know what is the idea of this postponement. Can he at least indicate by what time the Government propose to really start the work on the project ?